दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 01 मई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 210

महत्वपूर्ण एवं खास

न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित

नईदिल्ली (आरएनएस)। जाने-माने न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। नोएडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफी लोगों ने शोक जाहिर किया है।

नौसेना ने कोविड से निपटने अहमदाबाद में 57 सदस्यों का चिकित्सा दल तैनात किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। वर्तमान समय में चल रहे कोविड संकट का सामना करने और नागरिक प्रशासन की सहायता करने के प्रयासों में सशस्त्र सैन्य बलों के योगदान के एक अंश के रूप में नौसेना के एक चिकित्सा दल को कल 29 अप्रैल 2021 को अहमदाबाद से रवाना किया गया है। 57 सदस्यीय इस दल में 04 चिकित्सक, 07 नर्सें, 26 सहयोगी चिकित्साकर्मी (पैरामेडिक्स) ओर 20 सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं। यह दल कोविड संकट का सामना करने के लिए बनाए गए विशेष चिकित्सालय प्रधानमंत्री देखरेख कोविड चिकित्सालय (पीएम केयर्स कोविड हॉस्पिटल) में तैनात किया जाएगा। शुरू में इस दल की तैनाती दो महीने के लिए की गई है और आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को आगे भी बढाया जा सकेगा।

हल्के व बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार देश में कोविड-19 से निपटने और प्रबंधन करने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय और सहयोग के साथ काम कर रही है। कोविड-19 से बचाव, रोकथाम और प्रबंधन के लिए कई रणनीतिक और उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज इस विषय पर जारी दिशा-निर्देशों (2 जुलाई 2020) के स्थान पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, नैदानिक जांच में चिन्हित हल्के/बिना लक्षण (एसिम्प्टोमेटिक) वाले मरीज़ों को होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है।

नागरिक उडडयन मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए तेलंगाना को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी

नईदिल्ली (आरएनएस)। नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने तेलंगाना सरकार को ड्रोन की तैनाती के लिए सशर्त छूट दी है।इसके तहत ड्रोनों का उपयोग करके विजुअल लाइन ऑफ साइट (वीएलओएस)दायरे के भीतरकोविड-19 टीकों का प्रायोगिक वितरण करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इस अनुमति में छूट एक साल या अगले आदेश तक मान्य है।वहीं ये छूटें तभी मान्य होंगी, जब संबंधित संस्थाओं के लिए निर्धारित सभी शर्तों एवं सीमाओं का सख्ती से पालन किया जाएगा। ये परीक्षणऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आबादी, आइसोलेशन की स्थिति और भूगोल आदि जैसी परिस्थितियों का आकलन करने में सहायता करेंगे, जहां विशेष रूप से ड्रोन वितरण की जरूरत है।

टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कोविन पोर्टल पर दो करोड़ 45 लाख से अधिक ने पंजीकरण कराया

नईदिल्ली (आरएनएस)। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए 28 अप्रैल से शुरू हुए पंजीकरण के बाद 2.45 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। 28 अप्रैल को 1.37 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था। वहीं 29 अप्रैल को 1.04 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने नाम पंजीकृत कराये। इस बीच, देश में कोविड वैक्सीन की खुराक लेने वालों की कुल संख्या आज 15.22 करोड़ को पार कर गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर 15,22,45,179 वैक्सीन खुराक 22,43,097 सत्रों के माध्यम से दी गई हैं। इनमें 93,86,904 स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने पहला टीका लगवा लिया है और 61,91,118 स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं, जिनको दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है।

अग्रिम पंक्ति के 1,24,19,965 कार्यकर्ताओं को टीके की पहली डोज दी गई है और 67,07,862 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,19,01,218 पात्र लाभार्थियों ने पहला टीका लगवा लिया है तथा 1,04,41,359 पात्र लाभार्थियों ने टीके की दूसरी खुराक भी ले ली है। 45 से 60 साल उम्र के 5,17,78,842 लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है जबकि 34,17,911 लोग दूसरा टीका भी लगवा चुके हैं। देश में अब तक कुल टीकाकरण की 67.08 प्रतिशत खुराक दस राज्यों के लोगों को दी गई हैं। टीकाकरण अभियान दिन के 104वें दिन (29 अप्रैल, 2021 को) 22,24,548 टीके लगाए गए। टीकाकरण के 21,810 सत्रों में 12,74,803 पात्र लाभार्थियों को पहला टीका लगाया गया और 9,49,745 लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में, पिछले 24 घंटों में 19 लाख (19,20,107) से अधिक नमूनों की जांच की गई, यह भारत में की गई सर्वाधिक कोविड नमूनों की जाँच की संख्या है। भारत में आज तक 1,53,84,418 कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 81.99 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,97,540 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। उपचार से ठीक होने वाले 76.61 प्रतिशत लोग दस राज्यों से ही हैं। पिछले 24 घंटों में 3,86,452 नए मामले दर्ज किए गए। नए मामलों में 73.05 प्रतिशत रोगी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे दस राज्यों से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 66,159 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद केरल से 38,607 और उत्तर प्रदेश में 35,104 नए मरीज सामने आए।

भारत में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 31,70,228 तक पहुंच गई है। यह देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 16.90 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 85,414 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के कुल सक्रिय मामलों में 11 राज्यों का 78.18 प्रतिशत हिस्सा है।

देश में कोविड से मृत्यु दर कम हो रही है और वर्तमान में यह 1.11 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,498 कोविड मरीजों की मौत हुई है। अब हो रही मौतों में 77.44 प्रतिशत रोगी दस राज्यों से हैं। महाराष्ट्र में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 771 रही है। वहीं दिल्ली में 395 लोगों की मृत्यु हुई है। चार राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी रोगी की मौत की सूचना नहीं है। ये दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, नगालैंड, त्रिपुरा एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज (निमहंस) मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का समाधान प्रदान करने और महामारी के दौरान मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक टोल फ्री 24 × 7 हेल्पलाइन (080-4611 0007) संचालित कर रहा है।

राजनाथ ने सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान की

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं ताकि उन्हें देश में वर्तमान कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सशक्त किया जा सके। ये शक्तियां फॉर्मेशन कमांडरों को महामारी के खिलाफ चल रहे प्रयासों के लिए विभिन्न सेवाओं और कार्यों के प्रावधान के अलावा क्वारंटीन सुविधाएं/ अस्पताल स्थापित और संचालित करने, उपकरण / वस्तुओं / सामग्रियों / दुकानों की खरीद और उपकरणों की मरम्मत के कार्य संबंधी गतिविधियों में मदद करेंगी।

यह संपूर्ण शक्तियां सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों जिनमें चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी), जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ्स और तीनों सेवाओं में समकक्षों को दी गई हैं। जबकि कोर कमांडर/ एरिया कमांडरों को 50 लाख रुपये प्रति केस और डिवीजन कमांडरों/ सब एरिया कमांडरों और उनके समकक्षों को 20 लाख रुपये प्रति मामले तक के अधिकार दिए गए हैं। इन शक्तियों को शुरू में 1 मई से 31 जुलाई तक तीन महीनों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। ये पिछले सप्ताह सशस्त्र बलों के चिकित्सा अधिकारियों को सौंपी गई आपातकालीन शक्तियों के अतिरिक्त हैं।

पिछले वर्ष जब कोविड-19 महामारी पहली बार सामने आई थी, तब भी सशस्त्र बलों को यह आपातकालीन शक्तियां स्वीकृत की गई थीं। इसने सशस्त्र बलों को तेजी से और प्रभावी तरीके से स्थिति से निपटने में मदद की थी।

केन्द्र ने देश में रेमडेसिविर की कमी दूर करने अन्य देशों से आयात शुरू किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार ने देश में रेमेडिसविर की कमी को दूर करने के लिए दूसरे देशों से महत्वपूर्ण दवा रेमेडिसविर का आयात शुरू किया है। इसके तहत आज रेमेडिसविर की 75,000 शीशियों की पहली खेप भारत पहुंचेगी।

भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने अमेरिका के मेसर्स गिलियड साइंसेज इंक और मिस्र की फार्मा कंपनी मेसर्स ईवीए फार्मा को रेमेडिसविर की 4,50,000 शीशियां बनाने का ऑर्डर दिया है। अमेरिका से अगले एक या दो दिनों में 75,000 से 1,00,000 शीशियां भारत पहुंचेगी। इसके अलावा 15 मई से पहले एक लाख शीशियों की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ईवीए फार्मा शुरुआत में लगभग 10,000 शीशियों की आपूर्ति करेगी, जिसके बाद हर 15 दिन या जुलाई तक 50,000 शीशियां मिलेंगी।

सरकार ने देश में भी रेमेडिसविर की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है। 27 अप्रैल तक सात लाइसेंस प्राप्त घरेलू निर्माताओं की उत्पादन क्षमता प्रति माह 38 लाख शीशियों से बढ़कर 1.03 करोड़ शीशियों प्रति माह हो गई। पिछले सात दिनों (21-28 अप्रैल, 2021) में दवा कंपनियों द्वारा देश भर में कुल 13.73 लाख शीशियों की आपूर्ति की गई है। दैनिक आपूर्ति 11 अप्रैल को 67,900 शीशियों से बढ़कर 28 अप्रैल. 2021 को 2.09 लाख शीशियों तक पहुंच गई है। गृह मंत्रालय द्वारा रेमेडिसविर आपूर्ति को सुचारू रूप से करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाजरी जारी की गई थी।

सरकार ने भारत में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेमेडिसविर के निर्यात पर भी रोक लगा दी। आम लोगों के बीच इंजेक्शन की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीपीए ने 17 अप्रैल, 2021 को संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य जारी किया, जिससे सभी प्रमुख ब्रांडों की लागत 3500 रुपये प्रति शीशी से नीचे आ गई।

रेलवे ने अब तक 4 राज्यों में 664 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन आपूर्ति की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा जारी है और यह बड़ी संख्या में जीवन रक्षण का आधार बन रही है। राज्य सरकारों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने और अधिक संख्या में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की पूरी तैयारी कर ली है।

मध्य प्रदेश में आज दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचेगी। बोकारो से चार टैंकरों में 47.37 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई यह गाड़ी सागर और जबलपुर में आपूर्ति करेगी। यह रेलगाड़ी 29 अप्रैल को बोकारो से रवाना हुई और बिना किसी व्यवधान के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। इसके आज शाम तक निर्धारित स्थानों पर पहुँचने की संभावना है।

हरियाणा जल्द ही अपनी पहली और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त करेगा। एक रेलगाड़ी ओडिशा के राऊरकेला से 3 टैंकरों में 47.11 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर निकली है जबकि दूसरी अंगुल से 2 टैंकरों में 32 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई है। यह दोनों रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय में हरियाणा के लोगों की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल्द ही निर्धारित स्थानों पर पहुँच जाएंगी।

उत्तर प्रदेश लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मदद से अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए जल्द ही 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से रवाना होने वाली है। यह गाड़ी तीन टैंकरों में तरल ऑक्सीजन लेकर गंतव्य पर पहुंचेगी। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति को और तेज़ करने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 फीट के आईएसओ कंटेनर्स से तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति जमशेदपुर से लखनऊ के लिए करने हेतु अनुरोध किया है। आईएसओ कंटेनर्स के परिवहन हेतु अतिरिक्त सावधानी और योजना की आवश्यकता होती है और रेलवे अधिकारी आईएसओ कंटेनर्स कीसुरक्षित आपूर्ति के लिए उपलब्ध बेहतर विकल्पों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। संभावना है कि आईएसओ कंटेनर्स की लोडिंग 1 मई, 2021 को जमशेदपुर में शुरू हो सकती है।

भारतीय रेलवे ने अब तक कुल 664 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 356.47 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 64 मीट्रिक टन और दिल्ली को 70 मीट्रिक टन की आपूर्ति शामिल है। हरियाणा और तेलंगाना भी जल्द ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त करेंगे।

वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 15 हजार करोड़ तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया

» पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय

नईदिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त रकम प्रदान करने का फैसला किया है। व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना पर नए दिशानिर्देश जारी किए है।

इससे पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी कि केंद्र बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करने को लेकर अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को आगे बढ़ाने का उपाय करेगा।

पूंजीगत व्यय विशेष रूप से गरीबों एवं अकुशल लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है और इसका उच्च बहुगुणक प्रभाव होता है। इसके अलावा यह अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और आर्थिक वृद्धि की उच्चतर दर के रूप में इसके परिणाम दिखाई देते हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद पिछले साल पूंजीगत व्यय को लेकर राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना शुरू करने का फैसला लिया गया था।

सरकार के सभी शाखाएं एकजुट होकर कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपट रहे हैं: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह बात रेखांकित की गई कि वर्तमान महामारी संकट दरअसल 'सदी में एक बार होने वाला संकट' है और इसने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। बैठक के दौरान कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार के 'टीम इंडिया' दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और भारत के लोगों के सामूहिक प्रयासों पर आधारित है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार की सभी शाखाएं या इकाइयां एकजुट होकर और बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने मंत्रियों से अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क में रहने, उनकी मदद करने और उनसे निरंतर आवश्यक जानकारियां एवं सूचनाएं प्राप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों का तुरंत पता लगाया जाए और उन्हें जल्द-से-जल्द सुलझाया जाए। मंत्रिपरिषद ने पिछले 14 महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों एवं भारत के लोगों द्वारा किए गए समस्त प्रयासों की भी समीक्षा की।

अस्पतालों में बेड, पीएसए ऑक्सीजन सुविधाएं, इत्यादि बढ़ाने के रूप में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण, ऑक्सीजन के उत्पादन, भंडारण एवं ढुलाई से संबंधित मुद्दों को सुलझाने, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों से निपटने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ आपसी सामंजस्य से किए गए प्रयासों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस दौरान दी गई।

खेती-किसानी के विकास में राज्यों को किसी तरह की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी: तोमर

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि का क्षेत्र हमारे देश की बड़ी आबादी को कवर करने के साथ ही रोजगार प्रदान करता है। हमारे गांवों व कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिसके सहारे हम अनेक प्रतिकूलताओं से उबरते हैं। कृषि क्षेत्र ने तमाम प्रतिकूलताओं में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। किसानों के परिश्रम, भारत सरकार की कृषि हितैषी नीतियों व राज्य सरकारों के प्रयत्नों से कृषि क्षेत्र ने सकारात्मक योगदान दिया है और जीडीपी में भी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ प्रतिकूलताओं के बावजूद बढ़ी है।

तोमर ने कहा कि खेती-किसानी के विकास के लिए राज्यों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी, भारत सरकार राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रहेगी।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात शुक्रवार को राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में कही। तोमर ने खरीफ की अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं देते हुए राज्यों से आग्रह किया कि खेती के क्षेत्र में देश में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, तिलहन व दलहन की दृष्टि से भी सभी को और मिल-जुलकर, मिशन मोड पर काम करना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार सबके सहयोग से काम कर रही है और उम्मीद है कि हम इनमें भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तोमर ने सराहना की कि सभी किसानों व राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है तथा आशा जताई कि आगे भी योजनाबद्ध ढंग से काम करते रहेंगे। उन्होंने जैविक खेती व जीरो बजट खेती को लेकर भी मार्गदर्शन दिया तथा सभी राज्यों में आर्गेनिक खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया। तोमर ने कहा कि राज्यों को पहचान करना चाहिए कि वे कौन-कौन से हिस्सों को पूरी तरह आर्गेनिक कर सकते हैं तथा किसानों को समय पर मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं। देश में 307 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल करने के लिए तोमर ने शुभकामनाएं दी।

खरीफ सम्मेलन में राज्यों ने भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दी गई छूट से किसानों को बिना किसी बाधा के कृषि कार्य करने की सुविधा मिली है। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श से महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने, कृषि आदानों का मूल्यांकन और आवश्यकता एवं उनकी स्थिति का पता लगाने में सहायता हुई, जिससे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सम्मेलन से देश में खाद्य उत्पादन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप और कार्यनीति विकसित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी, सचिव संजय अग्रवाल, कृषि उत्पादन आयुक्त एस.के. मल्होत्रा तथा कृषि व उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही राज्यों के संबंधित अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।